

पुतिलिपि आदेशादिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिखरे
तदस्य राजस्व मण्डल मज्जु नवाखिर पुज्जु निगा 3105-तान/14
विरुद्ध आदेशादिनांक 25-6-13 पारित द्वारा अर आयुक्त नागर
सभाग सार पुज्जु 731/अ-6/2008-2009.

मोहनलाल तन्क भैरव यादव
निवासी ग्राम जिरीला तहसील
जिला धरमपुर जिला टोकमगढ मज्जु --- आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीलाल तन्क विण्जे यादव
निवासी ग्राम जिरीला तहसील
बडागाव धरम जिला टोकमगढ अनिय-3 -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3105 / 111 / 2014

जिला टीकमगढ़

स्थान
तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों
अभिभाषक
हस्ताक्षर

17.6.2017

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 731/अ-6/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 25 जून 2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि ग्राम डिकोली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 864 लगायत 870 कुल किता 7 कुल रकबा 3.095 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) अधार, लखन एवं गंगा यादव ने नीलामी में कय की है और सिविल न्यायालय ने आदेश दिनांक 26-12-58 में केवल भैयालाल को काविज होना माना है भूमिस्वामी नहीं माना है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने रिकार्ड की हेराफेरी की जांच हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार बड़ागांव को प्रत्यावर्तित किया है किन्तु अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने निगरानी क्रमांक 77/04-05 में पारित आदेश दिनांक 26-6-06 से एस0डी0ओ0 के विधिवत् आदेश को निरस्त करने में गलती की है और जब अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष अपील की गई, अपर आयुक्त ने न्याय नहीं किया है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया जावे।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध

अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि व्यवहार वाद कमांक 136/58 में पारित आदेश दिनांक 26-12-1958 के अनुष्रण में अपर कलेक्टर ने अनावेदक कमांक 1 भैयन पुत्र बिज्जे को वादग्रस्त भूमि का मालिक एवं काविज माना है , जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय के आदेश को अनदेखा करके आदेश पारित किया है । व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है, जिसके कारण अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 77/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-6-06 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-6-2006 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।


सदस्य